सं.ए-45011/3/2022-प्रशासन III

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आ.का.) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीआईपीएएम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त।
14. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (सी एंड सी/एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/जेएस (सी एंड सी और ओएमआई))/जेएस (बजट)/जेएस (आईपीपी/जेएस (आईएसडी)/जेएस (इनवेस्ट)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2022

सं.ए-45011/3/2022-प्रशा.III

वित्त मत्रांलय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषय: मई, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

बृहत आर्थिक अवलोकन:

31 मई, 2022 को जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान में वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8.7 प्रतिशत पर रखा है। यह महामारी से पूर्व वर्ष 2019-20 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से 1.5 प्रतिशत अधिक है, जो भारत के पूर्ण आर्थिक सुधार को स्थापित करती है।

भारत के साथ-साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति महामारी प्रेरित मांग प्रोत्साहन और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति-पक्ष के झटकों से उत्पन्न हुई है। उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, आरबीआई सहित सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक सख्ती का सहारा लिया है। इसने दुनिया भर की वैश्विक एजेंसियों को अलग-अलग देशों के विकास पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को भी संशोधित करके कम किया गया है, लेकिन अधिकांश एजेंसियां अभी भी इसे 7 प्रतिशत से ऊपर रखती हैं, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

भारत में उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति-पक्ष के झटके के कारण है और ग्रीष्म माह की गर्मी की लहर की शुरुआत ने भी खाद्य कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.79 प्रतिशत से घटकर मई में 7.04 प्रतिशत हो गई है, साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति भी दो महीनों के बीच 8.31 प्रतिशत से गिरकर 7.97 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में 15.08 प्रतिशत से बढ़कर मई में 15.88 प्रतिशत हो गई है और इसमे कुछ वृद्धि भी हो सकती है, जिससे आने वाले महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का संकट गहरा प्रतीत होता है क्योंकि उनके केंद्रीय बैंक इसका और अधिक आक्रामक तरीके से समाधान करते हैं। इसलिए भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी की वृद्धि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करने वाले एक प्रशंसनीय परिदृश्य के रूप में उभरता है। यह उस समय होगा जब महंगे आयात के कारण चालू खाता घाटा बढ़ने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता बढ़ रही है। इससे रुपये पर और दबाव पड़ेगा जो एक डॉलर के लिए लगभग 78 रुपये है। एक मूल्यह्रास विनिमय दर और चालू खाता घाटा बृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता को प्रभावित करने के लिए एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सरकार का राजकोषीय घाटा समाहित है और इसे वर्ष 2021-22 के बजट में निर्धारित राजकोषीय पथ से अलग नहीं होना चाहिए, जिसे वृद्धि का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त कैपेक्स प्रावधान के साथ बनाया गया है। हालांकि, डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करना एक चुनौती होगी। सब्सिडी को अधिक सख्ती से और लक्षित तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार भारत के सामने निकट भविष्य में अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, आर्थिक विकास को बनाए रखना, मुद्रास्फीति को कम करना और भारतीय मुद्रा के उचित मूल्य को बनाए रखते हुए चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने की चुनौतियां हैं। हालाँकि, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भारत

अपने वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और टीकाकरण की सफलता के कारण इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।